



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, 8 जुलाई, 2009 / 17 आषाढ़, 1931

---

हिमाचल प्रदेश सरकार  
पर्यटन एवं नागरिक एवं उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जुलाई, 2009

**संख्या टी०एस०एम०-एफ(५)-१३/९७-II.**—यतः हिमाचल प्रदेश को सरकारी व्यय पर निम्नलिखित विर्तिदिष्ट भूमि जैसा कि विवरणी में दर्शाया गया है, को जनहित में अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या: टी०एस०एम०-एफ(५)-१३/९७-II दिनांक 21-11-2006 व अधिसूचना संख्या: टी०एस०एफ०-एफ(५)-१३/९७-II दिनांक 24-07-2007 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 व 6-7 के अन्तर्गत नामतः मुहाल जंगल मैहफूजा मैहदूहा, नालदेहरा,

तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नालदेहरा गोल्फ कोर्स के विस्तार हेतु जारी की गई थी, में जैसा कि नीचे दी गई विवरणी में विर्तिदिष्ट है, भूमि अर्जन कार्यवाही को सहर्ष वापिस लेते हैं।

### विवरणी

जिला शिमला	तहसील शिमला (ग्रामीण)	मुहाल जंगल मैहफूजा मैहदूहा नालदेहरा	खसरा न0 6	रकबा (हैक्टेयर)
शिमला (ग्रामीण)	नालदेहरा		110	0-01-55
			114	0-11-23
			96	0-01-16
			97	0-40-56
			102	0-00-84
			103	0-15-62
			104	0-05-21
			105	0-01-12
			106	0-01-46
			107	0-55-57
			108	0-01-62
			111	0-02-71
			112	0-08-09
			113	0-03-47
			115	0-03-46
			116	0-01-97
			117	0-01-24
			118	0-00-09
			119	0-00-46
			120	0-07-66
			126	0-00-91
		किता— 21 +1		1-66-00 +0-79-24
		कुल किता—	22	कुल रकबा:— 2-45-24 हैक्टेयर

आदेश द्वारा,  
(मनीषा नंदा),  
सचिव।

### IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 29th June, 2009*

**No. IPH(A)2(B)5-41/95.**—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant Higher Pay Scale of Rs. 12000

16350/- in favour of Sh. Yoginder Kumar Sharma, Senior Hydrogeologist, Retd., on completion of 16 years regular service as Junior Hydrogeologist and Senior Hydrogeologist w.e.f. 6.9.2005. This will be further subject to the verification by the Audit Department.

By Order,  
Sd/-  
Principal Secretary.

## निर्वाचन विभाग

### अधिसूचना

शिमला—171009, 6 जुलाई, 2009

**संख्या: 5-4/2006-ई0एल0एन0.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या: 5-23/86-ई.एल.एन., तारीख 29-10-2005 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध—“क” का संशोधन।**—(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2005 के उपाबन्ध “क” में :—

(क) स्तम्भ संख्या—4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 4550—150—5000—160—5800—200—7000—220—7220 /—रुपए।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 6825 /—रुपए (वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर) प्रतिमास।”

(ख) स्तम्भ संख्या—10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“यथा स्थिति शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या सीधी भर्ती द्वारा संविदा के आधार पर, ऐसा न होने पर सैकण्डमैट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।”

(ग) स्तम्भ संख्या 15—क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्त, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी:—

**(I) संकल्पना।**—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो को प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना।—मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

**(II) संविदात्मक उपलब्धियां।**—संविदा के आधार पर नियुक्त निर्वाचन कानूनगो को 6825/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 150/-रुपए (पद के वेतनमान के न्यूतनम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

**(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी।**—मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

**(IV) चयन प्रक्रिया।**—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति।**—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

**(VI) करार।**—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

**(VII) निबन्धन एवं शर्तें।**—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6825/-रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 150/-रुपए (पद के वेतनमान के न्यूतनम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावरण (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण, किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य नियम, पैशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।"

आदेश द्वारा,  
अनिल खाची,  
सचिव।

#### उपबन्ध—"ख"

निर्वाचन कानूनगो और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/ श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने निर्वाचन कानूनगो के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार **निर्वाचन कानूनगो** के रूप में.....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात .....दिन को स्वयंसेव ही पर्यावसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम .....रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगया गया है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त निर्वाचन कानूनगो, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त निर्वाचन कानूनगो को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावयसन (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त निर्वाचन कानूनगो, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ—साथ इ.पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैशान नियम तथा आचरण नियमों आदि के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:—

1. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)
2. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में:—

1. ....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

2. ....  
 ....  
 ....  
 (नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-4/2006 ELN, dated 6-7-2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

## ELECTION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-171009, 6th July, 2009

**No. 5-4/2006-ELN.**—In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Election Kanungo, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2005, notified vide Notification No. 5-23/86-ELN, dated 29-10-2005, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called “the Himachal Pradesh Election Department, Election Kanungo, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Second amendment) Rules, 2009”.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-“A”.**—(1) In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Election Department, Election Kanungo, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2005.—

(a) For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:—

**“(i) Pay scales for regular incumbents: Rs.4550-150-5000-160-5800-200-7000-220-7220.**

**(ii) Emoluments for contract employees: Rs. 6825/- per month (equal to initial of the pay scale + dearness pay)”.**

(b) For the existing provisions against Column No.10, the following shall be substituted, namely:—

**“100 % by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis as the case may be, failing which on secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Column No.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.**

(c) For the existing provisions against Column No.15(A), the following shall be substituted, namely:—

---

**“Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—**

**(I) CONCEPT.**—(a) Under this policy the, Election Kanungo in Department of Elections, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.**—The Chief Electoral Officer, H.P. after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.**—The Election Kanungo appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6825/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). An amount of Rs. 150/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.**—The Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh will be the Appointing and Disciplinary Authority.

**(IV) SELECTION PROCESS.**— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.**—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.

**(VI) AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS.**— (a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6825/-P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 150/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfers of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By order,  
ANIL KHACHI,  
Secretary.

#### ANNEXURE-“B”

#### FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE ELECTION KANUNGO AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH.

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_ Between Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ S/o/W/o/D/o Shri. \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

Contract appointee (herein- after called the **FIRST PARTY**). AND The Governor, Himachal Pradesh through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (here-in-after the **SECOND PARTY**).

Whereas, the **SECOND PARTY** has engaged the aforesaid **FIRST PARTY** and the **FIRST PARTY** has agreed to serve as a **Election Kanungo** on contract basis on the following terms and conditions:—

- That the **FIRST PARTY** shall remain in the service of the **SECOND PARTY** as a **Election Kanungo** for a period of one years commencing on day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the **FIRST PARTY** with **SECOND PARTY** shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on \_\_\_\_\_ and information notice shall not be necessary.
- The contractual amount of the **FIRST PARTY** will be Rs. \_\_\_\_\_ per month.

---

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Election Kanungo will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Election Kanungo. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Election Kanungo will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official, at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

**IN THE PRESENCE OF WITNESS:**

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Name and full address)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Name and full address)

Signature of the FIRST PARTY)

**IN THE PRESENCE OF WITNESS:**

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Name and full address)

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Name and full address)

Signature of the SECOND PARTY)

## निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 6 जुलाई, 2009

**संख्या: 5-12/2008-ई.एल.एन.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 5-16/97-ई.एल.एन., तारीख 29-5-2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध—“क” का संशोधन।**—(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध “क” में :—

(क) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 2520—100— 3220—110—3660—120— 4140/- रुपए (प्रारम्भिक आरम्भ 2620/-रुपए के साथ)।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 3780/-रुपए (वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर) प्रतिमास।”

(ख) स्तम्भ संख्या-10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“यथास्थिति, शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या सीधी भर्ती द्वारा संविदा के आधार पर, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।”

(ग) स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

**(I) संकल्पना।—**(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में चपरासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र के बाहर होना।—राज्य मुख्यालय के लिए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश तथा उनके अपने जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए सम्बद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (विभागाध्यक्ष) के माध्यम से सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएंगे और विहित अर्हताएं तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेंगे।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

**(II) संविदात्मक उपलब्धियां।—**संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी को 3780/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100/-रुपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

**(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी।—**राज्य मुख्यालय के लिए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश तथा उनके अपने जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए सम्बद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।

**(IV) चयन प्रक्रिया।—**संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध चयन समिति/अभिकरण या निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति।—**जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण या निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश, द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

**(VI) करार।—**अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

**(VII) निबन्धन एवं शर्तें।—**(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 3780/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 100/-रुपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावरण (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, अवकाश नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। वे इस स्तरमें यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।'

आदेश द्वारा,  
अनिल खाची,  
सचिव ।

उपाबन्ध—“ख”

चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश/जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....  
.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश/जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त).....(जिसे इसमें इनके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने चपरासी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार चपरासी के रूप में.....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम .....रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध

नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त चपरासी, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावरण (समाप्त) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चपरासी, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ—साथ इ.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को एफ0आर0—एस0आर0, अवकाश नियम, साधारण भविष्य नियम, पैशन नियम तथा आचरण नियमों इत्यादि के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

#### साक्षियों की उपस्थिति में:-

1. ....  
 ....  
 ....  
 (नाम व पूरा पता)

2. ....  
 ....  
 ....  
 (नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

#### साक्षियों की उपस्थिति में:-

1. ....  
 ....  
 ....  
 (नाम व पूरा पता)

2. ....  
 .....  
 .....  
 .....  
 (नाम व पूरा पता) \_\_\_\_\_

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-12/2008 ELN, dated 6-7-2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## ELECTION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171009 the 6th July, 2009.*

**No. 5-12/2008-ELN.**—In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide Notification No. 5-16/97-ELN, dated 29-5-2007, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called “the Himachal Pradesh Election Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2009”.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-“A”.**—(1) In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Election Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 :—

(a) For the existing provision against Column No.4, the following shall be substituted, namely:—

**“(i) Pay scales for regular incumbents: Rs.2520-100- 3220-110-3660-120-4140(With initial start of Rs.2620/-).**

**“(ii) Emoluments for contract employees: Rs. 3780/- per month (equal to initial of the pay scale + dearness pay)”.**

(b) For the existing provision against Column No.10, the following shall be substituted, namely:—

**“100 % by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis as the case may be, failing which by transfer. The contract employees will get emoluments as given in Column No.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.**

(c) For the existing provisions against Column No.15(A), the following shall be substituted, namely:—

---

**“Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—**

**(I) CONCEPT.**—(a) Under this policy the, Peon in Department of Elections, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for on year to year basis.

**(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/ HPSSSB.**—The Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh for State Headquarter and the concerned District Election Officer(DC) for their respective District Election Office, after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant posts on contract basis through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (Head of the Department) Election Department will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.**—The Peon appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.3930/-per month (which shall be equal to initial of the pay scale +dearness pay). An amount of Rs. 100/- (equal to annual encrease in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed, if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.**—The Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh in the case of State Headquarter and the concerned District Election Officer (DC) in the case of their respective District Election Office will be the Appointing and Disciplinary Authority.

**(IV) SELECTION PROCESS.**—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned selection committee/ agency or by the Election Department, Himachal Pradesh.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.**—As may be constituted by the concerned recruiting authority or by the Election Department, Himachal Pradesh. from time to time.

**(VI) AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS.**—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.3780/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale +dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 100/- (equal to annual encrease in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfers of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

By Order,  
ANIL KHACHI,  
*Secretary.*

ANNEXURE-“B”

**FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE PEON AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH ADDITIONAL CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH/ DISTRICT ELECTION OFFICERS (DCs) HIMACHAL PRADESH.**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_ between Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ S/o/W/o/D/o Shri. \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

Contract appointee (herein after called the **FIRST PARTY**). AND The Governor, Himachal Pradesh through Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh/District Election Officer (DC),..... (here-in-after the **SECOND PARTY**).

Whereas, the **SECOND PARTY** has engaged the aforesaid **FIRST PARTY** and the **FIRST PARTY** has agreed to serve as a **Peon** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the **FIRST PARTY** shall remain in the service of the **SECOND PARTY** as a **Peon** for a period of one years commencing on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the **FIRST PARTY**

with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on \_\_\_\_\_ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be \_\_\_\_\_ per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Peon** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official, at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.

**IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.**

**IN THE PRESENCE OF WITNESS:**

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Name and full address)
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Name and full address)

**(Signature of the FIRST PARTY)**

**IN THE PRESENCE OF WITNESS:**

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Name and full address)

**(Signature of the SECOND PARTY)**

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Name and full address)

\_\_\_\_\_

**PERSONNEL DEPARTMENT**

Appointment-II

NOTIFICATION

*Shimla-171 002 the 2nd July, 2009*

**No. Per(AP.B)B(2)-1/99-Pt.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Er. Prakash Misra, Engineer-in-Chief (Retd.) HPPWD, as Member of the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur for a period of five years from the date he enters upon his office or until he attains the age of sixty two years, whichever is earlier, on the Terms & Conditions as specified in the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Terms and Conditions (Chairman & Members) Rules, 1998, as amended from time to time.

By Order,  
ASHA SWARUP,  
*Chief Secretary.*

\_\_\_\_\_

**H. P. STATE JUDICIAL ACADEMY**  
Curzon House, Boileauganj, Shimla-5

NOTIFICATION

*1st July, 2009*

**Ref. No. HPSJA/Trg/Induction-VI/2009/8694-8703**

**Subject:— Relieving of Judicial Officers.**

Pursuant to the Notification No. HHC/GAZ/14-52/74-V-16781-803 dated 1-7-2009 Ms. Neha Kaisth, Civil Judge (Jr. Division) is posted as Civil Judge, (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate Court No. III, Ghumarwin and Ms. Kanika Chawla, Civil Judge (Jr. Division) is posted as Civil Judge (Jr. Division)-cum-Judicial Magistrate, Court No. II, Rohru, are hereby relieved from Academy today i.e. in the afternoon of 1st July, 2009 and detailed for practical training about

court working for three months with effect from 2-7-2009 under the supervision of the District and Sessions Judge, Bilaspur and Shimla, respectively.

By Order,  
Sd/-  
Director.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जुलाई, 2009

**संख्या एफ0डी.एस-ए (3)6 / 91.**—भारत सरकार के कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की जी.एस.आर संख्या 800 के अधीन तारीख 09-06-1978 को प्रकाशित और उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति (नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग) की एस.ओ 681 (ई) और 682 (ई) के अधीन तारीख 30-11-1974 को प्रकाशित अधिसूचनाओं और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, अधिसूचना संख्या एफ0डी0एस-ए(1)-3-9 / 85 तारीख 26 जुलाई, 1989 द्वारा राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश कोयला अनुज्ञापन एवं मूल्य नियंत्रण आदेश, 1989 जारी किया था जिसे तारीख 16-09-1989 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था ।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना तारीख 12 फरवरी, 2007 के अधीन एस0ओ0 184 (ई) द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2006 (2006 का 54) लागू किया है, जिसके द्वारा कोयला, कोक और अन्य व्युत्पत्तियों पद का "आवश्यक वस्तु" की परिभाषा से लोप किया गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत करती है ।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
सचिव ।

[Authoritative English text of Notification No.FDS-A(3)-6/91, dated 07-07-2009 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].

**FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

Shimla-171002 the 07th July, 2009

**No. FDS-A(3)-6/91.**—Whereas *vide* notification No. FDS-A(1)3-9/85, dated, 26th July, 1989 the State Government had issued the Himachal Pradesh Coal Licensing and Price Control Order, 1989 in exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 read with section 5 of the said Act and the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) published under G.S.R.No. 800 dated 9<sup>th</sup> June, 1978 and in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-

operation) published under S.O.681(E) and 682 (E) dated 30.11.1994, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 16th September,1989 ;

Whereas *vide* S.O. 184(E) issued under notification dated 12th February, 2007, the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) has enforced Essential Commodities (Amendment) Act, 2006 (54 of 2006) whereby coal including coke and other derivatives have been deleted from the definition of the term essential commodity,”

Now, therefore in exercise of powers conferred by section 5 read with section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the said order with immediate effect.

By Order,  
Sd/-  
Secretary.

### निर्वाचन विभाग

#### अधिसूचना

शिमला—171009, 07 जुलाई, 2009

**संख्या: 5-37/2000-ई0एल0एन0.—**हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या: 5-37/2000-ई.एल.एन., तारीख 9 अक्तूबर, 2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग—I (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग—I (राजपत्रित) (प्रथम संशोधन) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध—“क” का संशोधन.—**(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध “क” में :—

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:— 7220—220—8100—275—10300—340—11660 /—रुपए।

“(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:— 10830 /— रुपए (वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर) प्रतिमास।”

(ख) स्तम्भ संख्या—10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“यथास्थिति शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या सीधी भर्ती द्वारा संविदा के आधार पर, दोनों के न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर। संविदा पर

नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा”।

(ग) स्तम्भ संख्या 15—क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी—

(I) संकल्पना— (क) इस पॉलिसी के अधीन निर्वाचन विभाग में प्रोग्रामर को प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:—सचिव (निर्वाचन) एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां—संविदा के आधार पर नियुक्त प्रोग्रामर को 10830/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 220/-रुपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी—सचिव (निर्वाचन) एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया—संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध चयन समिति/भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति—जैसी सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

(VI) करार—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्ते—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 10830/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 220/-रुपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावरण (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।”

आदेश द्वारा,  
अनिल खाची,  
संविव।

उपाबन्ध—“ख”

प्रोग्रामर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (निर्वाचन) एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘प्रथम पक्षकार’ कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, सचिव (निर्वाचन) एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘द्वितीय पक्षकार’ कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने उपरोक्त ‘प्रथम पक्षकार’ को लगाया है और ‘प्रथम पक्षकार’ ने प्रोग्रामर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रोग्रामर के रूप में.....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि

प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा.....तारीख को स्वयंसेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम .....रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त प्रोग्रामर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावर्सान (समाप्त) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त प्रोग्रामर, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ—साथ इ.पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैशान नियम तथा आचरण नियमों इत्यादि के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में—

1. ....  
.....  
.....

(नाम व पूरा पता)

2. ....  
 ....  
 ....  
 (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

## साक्षियों की उपस्थिति में:-

1. ....  
 ....  
 ....  
 (नाम व पूरा पता)

2. ....  
 ....  
 ....  
 (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-4/2006 ELN, dated 07-07-2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

**ELECTION DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171009, 7th July, 2009*

**No. 5-37/2000-ELN.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Programmer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide Notification No. 5-37/2000-ELN, dated 9-10-2007, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called “the Himachal Pradesh Election Department, Programmer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2009”.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-“A”.**— (1) In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Election Department, Programmer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 :-(a) For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:-

**“(i) Pay scales for regular incumbents:- Rs.7220-220-8100-275-10300-340-11660.**

**“(ii) Emoluments for contract employees: Rs. 10830/- per month (equal to initial of the pay scale + dearness pay).”**

(b) For the existing provisions against Column No.10, the following shall be substituted, namely:—

**“100% by promotion, failing which by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis as the case may be, failing both by secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Column No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column”.**

(c) For the existing provisions against Column No.15(A), the following shall be substituted, namely:—

**“Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below.—**

**(I) CONCEPT.**—(a) Under this policy the Programmer in Department of Elections, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:**— The Secretary (Elections) cum-Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.**—The Programmer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.10830/-per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). An amount of Rs. 220/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.**—The Secretary (Elections)-cum Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh will be the Appointing and Disciplinary Authority.

**(IV) SELECTION PROCESS.**—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned selection committee/ agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.**—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

**(VI) AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS.**—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.10830/-per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 220/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the

post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the Contract Appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfers of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract Appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of Contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By order,  
ANIL KHACHI,  
*Secretary.*

---

#### ANNEXURE-“B”

#### FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE PROGRAMMER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH SECRETARY (ELECTIONS)-CUM-CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH.

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_ between Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ S/o/W/o/D/o Shri. \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

Contract Appointee (herein- after called the **FIRST PARTY**). AND The Governor, Himachal Pradesh through Secretary(Elections) cum-Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (here-in-after the **SECOND PARTY**).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid **FIRST PARTY** and the **FIRST PARTY** has agreed to serve as a **Programmer** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Programmer** for a period of one years commencing on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on \_\_\_\_\_ and information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. \_\_\_\_\_ per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Programmer will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the Contractual Programmer. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A Contractual Programmer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Transfer of an incumbent appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official, at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.

**IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.**

**IN THE PRESENCE OF WITNESS:**

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)

**IN THE PRESENCE OF WITNESS:**

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Name and full address)

(Signature of the SECOND PARTY)

**REVENUE DEPARTMENT (PROJECT CELL)**

**NOTIFICATION**

*Shimla-2 the 11th June ,2009*

**No. Rev(PC)A(9)-2/2007.**—The, Governor, Himachal Pradesh is please to notify the Rehabilitation and Resettlement Plan, 2009 as per annexure-A, for resettlement & rehabilitation of families affected by Cement Plants to be established in Himachal Pradesh and shall come into force with immediate effect.

By Order,  
Sd/-  
*Additional Chief Secretary -cum-  
Financial Commissioner.*

\_\_\_\_\_  
ANNEXURE-“A”

**REHABILITATION AND RESETTLEMENT PLAN FOR SETTING UP OF CEMENT  
PLANT IN HIMACHAL PRADESH**

**CHAPTER-I**

**1. INTRODUCTION:**

This Rehabilitation & Resettlement Plan shall be implemented by the Project Authority under the control and supervision of Deputy Commissioner-cum-Administrator of the concerned district.

The Rehabilitation and Resettlement Plan will include not only those who directly lose land and other assets but also those who are affected by such acquisition of assets. The Project Authority

shall be at liberty to put in place greater benefit levels than those prescribed in the Rehabilitation & Resettlement Plan,2009.

## CHAPTER – II

### 2. NAME OF PLAN:

**2.1** This plan shall be called “The Rehabilitation and Resettlement Plan 2009 for the Project Affected Families consequent to the acquisition of land for establishment of cement plant.

**2.2** It shall extend to the whole of area affected or likely to be affected as result of construction of cement plant including the mining areas as well as the areas adjacent to the cement plant.

**2.3** It shall come in to force immediately .

## CHAPTER-III

### 3. DEFINITIONS:

**3.1** The definition of various expressions used in this Plan are as follow:—

(a) **“Administrator for Rehabilitation and Resettlement” means** an officer not below the rank of Deputy Commissioner of the district.

a. **“Affected Family” means:**

- (i) A family whose primary place of residence or other property or source of livelihood is adversely affected by the acquisition of land for a project or involuntary displacement for any other reason; or
- (ii) Any tenure holder, tenant, lessee or owner of other property, who on account of acquisition of land (including plot in the abadi or other property) in the affected area or otherwise, has been involuntarily displaced from such land or other property; or
- (iii) Any agricultural or non-agricultural labourer, landless person (not having homestead land, agricultural land, or either homestead or agricultural land), rural artisan, small trader or self-employed person; who has been residing or engaged in any trade, business, occupation or vocation continuously for a period of not less than three years preceding the date of declaration of the affected area, and who has been deprived of earning his livelihood or alienated wholly or substantially from the main source of his trade, business, occupation or vocation because of the acquisition of land in the affected area or being involuntarily displaced for any other reason.

c. **“Affected Area” means** area of villages notified by appropriate Government .

d. **“Agricultural labourer” means** a person primarily resident in the affected area for a period of not less than three years immediately before the notification of the affected area who does not hold any land in the affected area but who earns his livelihood principally by manual labour on agricultural land therein immediately before such declaration and who has been deprived of his livelihood.

e. “**Agricultural land**” includes land being used for the purpose of :

- (i) Agriculture or horticulture
- (ii) Dairy farming / Poultry farming Pisci-culture, breeding of livestock or nursery growing medicinal herbs;
- (iii) Raising of crops, grass or garden produce; and
- (iv) Land used by an agriculturist for the grazing of cattle, but does not include land used for cutting of wood only;

f. “**appropriate Government**” means ;

- (i) In relation to the acquisition of land for the purposes of the Union, the Central Government.
- (ii) In relation to a project which is executed by the Central Government Agency or under taking or by any other agency on the orders or directions of the Central Government.
- (iii) In relation to the acquisition of land for purposes other than (i) and (ii) above , the State Government ; and .
- (iv) In relation to the rehabilitation and resettlement of persons involuntarily displaced due to any reason the State Government;
- (g) “**BPL Family**” the Below Poverty Line (BPL) families shall be those as defined by the Planning Commission of India from time to time and included in a BPL list for the time being in force;
- (h) “**Commissioner for Rehabilitation& Resettlement**” means the Commissioner for Rehabilitation & Resettlement appointed by the State Government not below the rank of Commissioner or of equivalent rank of the Government
- (i) “**DDP block**” means a block identified under the Desert development Programme of the Government of India.
- (j) “**Family**” includes a person, his or her spouse, minor sons, unmarried daughter minor brother, unmarried sister, father, mother and other relatives residing with him or her and dependent on him or her for the livelihood; and includes “nuclear family” consisting of a person, his or her spouse and minor children ;
- (k) “**Holding**” means the total land held by a person as an occupant or tenant or as both ;
- (l) “**khatedar** “ means a person whose name is included in the Revenue records of the parcel of land under reference ;
- (m) “**Houseless family**” means a family who is rendered houseless as a result of acquisition of their house under the Land Acquisition Act, 1894.
- (n) “**Landless family**” means a family whose holding is reduced to 5 biswa or less after acquisition, whether as an owner or as tenant in the project affected area.
- (o) “**land acquisition**” or “**acquisition of land**” means acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 (of 1894), as amended from time to time, or any other Law of the Union or a State for the time being in force;
- (p) “**marginal farmer**” means a cultivator with an unmitigated land holding up to one hectare or irrigated land holding up to half hectare;
- (q) “**non-agricultural labourer**” means a person who is not an agricultural labourer but is primarily residing in the affected area for a period of not less than three years immediately before the declaration of the affected area and who does not hold any land under the affected area but who earns his livelihood principally by manual labour or as a rural artisan immediately before such declaration and who has been deprived of earning his livelihood principally by manual labour or as such artisan in the affected area;

---

- (r) “**notification**” means a notification published in the State Gazette of a State;
- (s) “**occupier**” means members of the Scheduled Tribes in possession of forest land prior to the 13th day of December, 2005.
- (t) “**Ombudsman**” means the person appointed under this Plan for redressal of grievances;
- (u) “**prescribed**” means, unless otherwise specified, prescribed by guidelines or orders issued by the State Government under this Plan;
- (v) “**Project**” means a project involving involuntary displacement of people, irrespective of the number of persons affected ;
- (w) “**resettlement area**” means any area so declared by the appropriate Government.
- (x) “**small farmer**” means a cultivator with an un-irrigated land holding up to two hectares or with an irrigated land holding up to one hectare, but more than the holding of a marginal farmer.

## CHAPTER-IV

### 1. DETAILS OF AFFECTED PERSONS / FAMILIES ETC.

The rehabilitation & Resettlement plan shall contain the following particulars:—

**4.1** The extent of land to be acquired for the project and the name(s) of the affected villages.

**4.2** A village-wise list of the affected persons, family-wise, and the extent and nature of land and immovable property owned or held in their possession in the affected area, and the extent and nature of such land and immovable property which they are likely to lose or have lost, indicating the survey numbers thereof subject to further amendments, if any.

**4.3** A list of agricultural labourers in such area and the names of such persons whose livelihood depends on agricultural activities subject to further amendments, if any;

**4.4** A list of persons who have lost or are likely to lose their employment or livelihood or who have been or likely to be alienated wholly or substantially from their main sources of trade, business, occupation or vocation consequent to the acquisition of land for the project or involuntary displacement due to any other cause subject to further amendments, if any;

**4.5** A list of non-agricultural labourers, including artisans subject to further amendments, if any;

**4.6** A list of affected landless families, including those without homestead land and below poverty line families subject to further amendments, if any;

**4.7** A list of vulnerable affected persons, subject to further amendments, if any;

**4.8** A list of occupiers, if any; subject to further amendments, if any.

**4.9** A list of public utilities and government buildings which are affected or are likely to be affected subject to further amendments, if any;

**4.10** Details of public and community properties, assets and infrastructure.

**CHAPTER-V****5. REHABILITATION AND RESETTLEMENT BENEFITS FOR THE PROJECT AFFECTED FAMILIES:**

**5.1** Land for Project shall be transferred or acquired at mutually agreed price between the Project Authority and land owners or if acquisition under the Land Acquisition Act is required compensation will be given as per prevailing market rate and compensation for built-up property will also be given on the market rate of the same specification.

**5.2** The Rehabilitation and Resettlement benefits shall be extended to all the affected families who are eligible as Project Affected Families on the date of publication of the notification U/s. 4 of Land Acquisition Act, 1894 as entered in the Panchayat Parivar register and any division of assets in the family after the said date will not be taken into account.

**5.3** The entire expenditure on rehabilitation and resettlement benefits and other expenditure for rehabilitation and resettlement of the affected families shall be borne by the Project Authority for which the land is being acquired. The Project Authority shall deposit the whole cost in lump-sum with Administrator i.e. Deputy Commissioner of concerned District within a period of thirty days from the date of announcement of award by the Land Acquisition Collector or as may be decided by the Administrator.

**5.4** It shall be the responsibility of the Project Authority to provide sufficient funds to the Administrator (Deputy. Commissioner of concerned district) for rehabilitation and resettlement of project affected families for proper implementation of the rehabilitation and resettlement Plan.

**5.5** The Administrator (Deputy. Commissioner of concerned district) for rehabilitation and resettlement shall keep proper books of accounts and records of the funds placed at his disposal and submit periodic returns to the appropriate Government in this behalf.

**5.6** The compensation award shall be declared and disbursed well in time before displacement of the affected families.

**5.7** Land being acquired for this project cannot be transferred to any other purpose including public purpose without prior approval of Govt. of HP.

**5.8 BENEFITS TO HOUSELESS FAMILIES OR HOUSELESS & LANDLESS FAMILIES:**

Any project affected family who has been rendered houseless or houseless & landless due to acquisition of house shall be entitled for the following benefits on the basis of nuclear family:

**5.8.1** Project Affected Family shall be allotted free of cost house site of total 150 Sq. Mtr. with a built up plinth area of 80 Sq. Mtr. to the each nuclear family. Alternatively,

- (i) A plot of size 150 Sq. Mtr. (Max.) which allows construction of built up house of 80 Sq. Mtr. plinth area in the Rehabilitation Colony (RC) plus construction cost of the house at the rate of Rs. 4500/- per Sq. Mtr. Which will be valid for one year and will be increased by 10% on annual basis.

OR

- (ii) A plot of size 250 Sq.Mtr. maximum in the Rehabilitation colony for construction of house for which lump sum construction grant of Rs. 3,00,000/- will be paid.

---

(iii) If the Project Affected family does not opt for house / plot but constructs house on their own plot at their own cost with a plinth area of 80 Sq. Mtr. Or more shall be paid a lump-sum amount of Rs. 4,50,000/-.

OR

Option from such families will be taken at an appropriate time.

#### **5.9 SUBSISTENCE ALLOWANCE:**

Each Project Affected (houseless / houseless & landless) family which is involuntarily displaced shall get a monthly subsistence allowance equivalent to 25 days minimum agricultural wages (@ Rs. 125/- per day) i.e. Rs.37,500/- OR agricultural wages as determined by the Agriculture Department, Govt. of H.P. whichever is more per month for a period of one year from the date of displacement.

#### **5.10 REHABILITATION GRANT :**

Each Project affected (houseless / houseless & landless) nuclear family who has not been provided direct / indirect employment shall be entitled to a rehabilitation grant equivalent to 750 days minimum agricultural wages or Rs. 1,00,000/- whichever is higher.

**5.10.1** The stamp duty and other fees payable for registration of land or house allotted to the affected family should be borne by the Project authority.

**5.10.2** The land or house allotted to the affected families under this policy shall be free from all encumbrances.

**5.10.3** The land or house allotted to the affected families under this policy may be in the joint names of wife and husband of the affected family.

#### **5.11 COW SHED GRANT :**

Each affected family that is displaced and has cattle shall get one time financial assistance of Rs. 50,000/- for construction of cattle shed.

#### **5.12 SHIFTING GRANT:**

- (i) Each Project Affected Family that is displaced shall get a one time financial assistance of Rs. 20,000/- for shifting of the family, building materials, belongings and cattle.
- (ii) The Project Affected Family shall shift within one months from the date of allotment of house constructed for the purpose of rehabilitation of affected family in the resettlement area.

OR

within a period of six months from the date of allotment of the house site in the resettlement area.

OR

if the affected family opts for lump-sum grant in lieu of house / house site shall shift within a period of two months from the date of receipt of one time grant.

### **5.13 FREE ISSUE OF CEMENT:**

**5.13.1** The project authority will provide 100 nos of Cement bags free of cost and 50 nos of Cement bags at 50 % of market rate for repairs / construction of house to each nuclear houseless family of the project affected area.

The above onetime benefit can be availed during the period of seven years, after three years of the commissioning of the plant, as per the procedure laid down by the DC/ SDM cum LAO concerned.

**5.13.2** All Project Affected Families will get rehabilitation grant of Rs.50,000/-.

### **5.14 LUMP-SUM BENEFITS IN LIEU OF NOT OPTING ALL OTHER BENEFITS HEREIN MENTIONED ABOVE:**

#### **A: HOUSELESS OR HOUSELESS & LANDLESS FAMILIES:**

The Project Affected Family which does not opt for the house as provided under clause no. 5.2 (i.e. Benefits to the houseless / houseless & landless families) herein above and other applicable benefits mentioned herein above may at their option take a lump-sum amount of Rs. 6,25,000/- in lieu of the above specified benefits.

### **5.15 BENEFIT TO B.P.L. FAMILIES WITHOUT HOMESTEAD LAND:**

**5.15.1** Each affected Below Poverty Line family (bonafide resident Himachali) which is without homestead land and which has been residing in the affected area continuously for a period of not less than three years preceding the date of declaration / notification U/s. 4 of Land Acquisition Act of the affected area and which has been involuntarily displaced from such area, shall be entitled to a house of 80 Sq. Mtr. built up area on 150 Sq. Mtr. plot in rural areas. In case, such affected family opts not to take the house offered, shall get a one time financial assistance of Rs. 3,50,000/- for house construction on their own plot.

**5.15.2** The Project Affected Scheduled caste/Scheduled tribes / O.B.C. families enjoying reservations benefits, if any, in the affected area shall be entitled to get the reservation benefits at the resettlement area.

## **CHAPTER-VI**

### **6.0 EMPLOYMENT OPPORTUNITIES:**

**6.1 DISCLOSURE OF MANPOWER REQUIREMENT.**—The Project Authority shall disclose the manpower requirement category-wise including management, operational and other personnel required during the construction period as well as when the plant is made operationalized by submitting in writing requirement to the Administrator i.e. Deputy Commissioner of concerned district within a period of three months from the date of approval of R&R policy OR within three months of declaration of Section-6 under Land Acquisition Act, 1894, whichever is earlier.

**6.1.1** The Administrator will further advertise the vacancies in the local newspapers for the information of the Project Affected families.

**6.1.2** Employment shall be provided by the Project Authority.

**6.1.3** The project authority will give employment to the Project affected families – at least one person per nuclear family, subject to the availability of vacancies and suitability of the affected person for employment including the sub-contractors employed during the construction period of the plant;

**6.1.4** Wherever necessary, the Project Authority shall arrange for training of the affected persons as per the requirement of project, so as to enable such persons to take on suitable jobs before handing over land as acquired for Company.

**6.1.5** The Project Authority shall offer scholarships and other skill development opportunities to the eligible persons from the affected families as per the criteria as may be fixed by the State Government of Himachal Pradesh.

**6.1.6** The Project Authority shall give preference to the affected persons or their groups or cooperatives in the allotment of contract including transportation job, shops or other economic opportunities in and around the project site.

**6.1.7** The Project Authority shall give preference to willing landless labourers and unemployed affected persons while engaging labour in the project during the construction phase.

**6.1.8** No family shall be entitled to give its right for consideration of employment to a member of some other family.

## **6.2 PROCEDURE FOR EMPLOYMENT:**

**6.2.1** Any Project affected family seeking employment in the Project shall submit application on the prescribed proforma in the office of Administrator for Rehabilitation and Resettlement (*i.e.* Deputy Commissioner of concerned district) or the officer authorized by him or Land Acquisition Officer as per the approval of Government alongwith required affidavit duly attested. Dates within which such applications are to be filed shall be fixed by the Land Acquisition Officer with prior approval of the Deputy Commissioner of concerned district as per the requirement of the Project Authority.

**6.2.2** A separate register shall be maintained in the office of Administrator for Rehabilitation and Resettlement Plan or Land Acquisition Officer where the particulars of each affected family will be entered on the basis of particulars filled in application and as per Panchayat Parivar Register.

**6.2.3** The Administrator for Rehabilitation and Resettlement Plan / Deputy Commissioner of concerned district shall approve the mohal-wise list of affected families eligible for employment and the Project Authority will consider the list for employment depending upon the number of vacancies as determined by the Project Authorities.

**6.2.4** Form of application along with specimen of affidavit shall be supplied to each head of family by the Cement Project Authority free of cost.

## **6.3 PREFERENCE OF EMPLOYMENT:**

The following criteria will be adhered to by the Deputy Commissioner concerned for giving preference while sponsoring the names for employment :—

---

- (i) The affected families rendered houseless and/or landless on account of acquisition of their land whose land before acquisition was more than 10 Bighas and after acquisition are left with 5 biswa or less;
- (ii) The families rendered houseless and/or landless on account of acquisition of their land whose land before acquisition was less than 10 Bighas but more than 5 Bighas and after acquisition are left with 5 biswa or less;
- (iii) The families whose land before acquisition was less than 5 bigha but more than 5 biswa and after acquisition are left with less than 5 biswa;
- (iv) The families whose land acquired is less than 5 biswa;
- (v) Others viz. rural artisan, small trader or self-employed persons, agricultural / non-agricultural labours etc.

**6.3.1** The company shall have to employ at least 70% bonafide residents of Himachal Pradesh in accordance with the H.P. Government's policy. In the event of non-availability of the requisite expert, technical and managerial manpower with requisite qualification, non-availability certificate will be obtained from the Administrator for Rehabilitation and Resettlement / Land Acquisition Officer.

#### **6.4 SECONDARY EMPLOYMENT:**

**6.4.1** If for practical reasons it is not possible for the Project Authorities to provide direct employment to all the affected families due to availability of lesser vacancies / requirement, every affected family shall have to be helped in starting some gainful occupation by way of providing training. Therefore, such affected families who could not be accommodated in direct employment, the Project Authorities will help them in one of the following manner:

**6.4.2** The Project authorities will construct shopping complexes in which preference will be given to those affected families which could not be accommodated in direct employment in the Company in allotting these shops but for this the Project Authority can construct only up to 25 shops in the project affected area. Only after obtaining NOC from the Administrator, these shops shall be allotted to the families / people other than the project affected families.

**6.4.3** Some members of the project affected families may qualify for vocational training courses like ITI etc. The Project Authority shall bear the cost of their training including tuition, residential hostel charges, books and stationery charges as fixed by the Project Authority. However, the Company shall be under no obligation to give employment to the persons so trained.

**6.4.4** The project authorities will also award petty contracts including transportation work to the Co-operatives of affected families on preferential basis, provided their rates are competitive. The project authorities shall ensure that eligible persons from affected families are engaged by their contractors on a preferential basis during the construction/ operational stage.

**6.4.5** The Project Authority shall provide necessary training facilities for development of entrepreneurship so as to enable Project Affected Families to take up self-employment.

**6.4.6** All the above measures for providing of employment shall also be applicable to the contractors and sub-contractors of the Project Authority at the time of construction of the cement plant.

### **CHAPTER-VII**

#### **7. ANNUITY TO VULNERABLE PERSONS:**

The Project Authority shall at their cost arrange for annuity policy that will pay a pension minimum @ Rs.700/- per month for ten years or till he/she is employed, whichever is earlier, to vulnerable affected persons.

**CHAPTER-VIII****8. AMENITIES AND INFRASTRUCTURE FACILITIES TO BE PROVIDED AT RESETTLEMENT AREA:**

**8.1** Constructed houses alongwith the infrastructural facilities, as specified herein below, will be provided by the project authority in the resettlement colony provided a minimum of 50 families opt for the constructed houses of 80 sq. mtr. plinth area on the plot of 150 Sq. Mtr. in lieu of acquisition of house in the resettlement colony.

Infrastructural facility in the resettlement area shall, inter alia, include road, drainage and sewerage system, drinking water supply, road side tree plantation, electricity, schools, dispensary etc. will be provided at project cost. If any available infrastructure is damaged due to the construction of the project, it will be restored by the project authority. This includes water supply. Irrigation, roads, paths, schools, places of worship, community building etc. The local people will be allowed use of the infrastructure created primarily for the project like roads, bridges, schools etc.

**8.2 Medical facilities :**

- (a) A medical fund will be created for the Project Affected Families. This fund will be used for providing treatment to the members of Project Affected Families in hardship due to illness or in extreme illness or accident cases. Medicines may also be provided to other residents in the area.
- (b) Free medical treatment will be provided to Project Affected Families at the project medical facility.
- (c) Medical camps will be organized in various places in the project affected zone from time to time.

**8.3 Fuel supply :**

If it is felt that the fuel supply of the local residents is effected due to construction of the project, a scheme will be formulated to provide alternative fuel or fuel saving devices to the families whose fuel supply is effected.

**8.4 Identity card:**

Each Project Affected Family will be given an identity card which will have names of all the members of Project Affected Family.

**8.5 Cultural fund :**

Project authorities will set up a cultural fund for providing grants for organizing local fairs, festivals and functions.

**CHAPTER-IX****9. INDEXATION OF REHABILITATION GRANT AND OTHER BENEFITS:**

The rehabilitation grant and other benefits expressed in monetary terms in this policy shall be indexed to the Consumer Price Index (CPI) with the 1st day of April following the date of coming in to force of this policy as the reference date.

## CHAPTER-X

### 10. UPGRADATION / WIDENING OF EXISTINGROADS(s) OR CONSTRUCTION OF SEPRATE ROAD FOR PLYING OF TRUCKS:

Project Authority will ensure the upgrade/ upgradation/widening of the existing road connecting to their project site at their cost. However, if the existing road is not found suitable / feasible for upgraded / widening then alternate road connecting to National Highway/ State Highway etc. from Project site will have to be constructed as per the terms and conditions mutually decided between Government of HP and Project Authority.

## CHAPTER-XI

### 11. PERIPHERY DEVELOPMENT:

**11.1** A District Level Project Area Development Advisory Committee (DPADC) under the Deputy Commissioner of concerned district shall be constituted by the Government of Himachal Pradesh with representatives of the State Government, Executing Agency / Project Authority, Land Oustees, Gram Panchayat concerned for monitoring and implementing the above schemes. As per MOU signed between Government of Himachal Pradesh and the Project Authority, the Project Authority shall be bound to make a provision of 1.5% of final cost of project towards Local Area Development Authority. The amount on this account shall be deposited by the Project Authority with the Deputy Commissioner of concerned (Chairman of DPADC) in equal annual installments during the construction period of the project and shall be payable in the 1st quarter of every financial year. This fund shall be utilized by the Deputy Commissioner in consultation with the DPADC for construction of various Community Development assets including School, Health Centre, Ayurvedic Dispensary, Veterinary Dispensary etc. in the Project Affected area.

In addition to this, after commissioning of the plant the Project Authority shall contribute towards the Socio-economic development of the areas contiguous to the area of operation and for this purpose the fund shall be earmarked in consultation with / approval of Government of H.P.

The Project Authorities shall also ensure creation of parking space for at least 100 commercial heavy vehicles near the plant site for parking of vehicles to be used for transportation of cement along with provision of commercial space for creation of infrastructure for repair and maintenance of these vehicles.

## CHAPTER XII

### 12. REDRESSAL MECHANISM:

**12.1** The Himachal Pradesh Govt. shall constitute a committee under the Chairmanship of Dy. Commissioner of concerned district to monitor and review the progress of implementation of the Scheme/ Rehabilitation and Resettlement Plan and to carry out post implementation social audit.

**12.2 Ombudsman:**

- (a) An Ombudsman shall be appointed by the Govt. of HP in the manner as may be prescribed for time bound disposal of the Grievances arising out of the matters covered by this policy.
- (b) Any affected person, if aggrieved, for not being offered the admissible rehabilitation and resettlement benefits, as provided under this Plan, may move an appropriate petition for redressal of his or her grievances to the Ombudsman concerned.